...ताकि उत्तर प्रदेश में किसान रहें खुशहाल

■ उप्र में कृषि और किसानों के लिए ढेरों योजनाएं

■ योजनाओं की निगरानी व्यवस्था भी की मजबूत

■ सूखा प्रभावित इलाकों के लिए चारा दाना कार्यक्रम, किसानों को मिलेगा तीन फीसद की दर से कर्ज

■ बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों में ट्यूबवेल के लिए 500 करोड़

■ 40 हजार तालाबों को किया जा रहा पुनर्जीवित

■ कृषि और किसानों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध : अखिलेश

"उत्तर प्रदेश की तरक्की एवं खुशहाली का रास्ता प्रदेश के गांव एवं किसानों के विकास से जुड़ा हुआ है" -अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

लखनऊ (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश में कृषि योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है। इतना ही नहीं प्रदेश शासन से लेकर जिलास्तर तक के अधिकारी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मंशा के अनुरूप किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए बनाई गई ढेरों योजनाओं के क्रियान्वयन में जुटे हुए हैं। इन योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में भी धन का व्यापक इंतजाम किया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि उत्तर प्रदेश की तरक्की एवं खुशहाली का रास्ता प्रदेश के गांव एवं किसानों के विकास से जुड़ा हुआ है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया था ताकि किसानों की समस्याओं का प्रभावी समाधान करने के साथ ही उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इसके मद्देनजर सरकार ने कृषि और किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं चलाईं और उनके लिए धन का भी आवंटन किया। वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि योजनाओं और किसानों के हित में आवंटित किए गए धन के उपयोग आदि को लेकर निगरानी व्यवस्था भी मजबूत की गई ताकि योजनाएं वित्तीय वर्ष के अंत में अपने शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और यहां के किसान ही विकास की दिशा तय करते हैं। यही वजह है कि इस बार के बजट में भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल खोल कर किसानों के हित में पैसे आवंटित किए हैं। एक तरफ जहां उन्होंने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए चारा दाना कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वहीं तीन फीसद की दर से किसानों को कर्ज देने की घोषणा की गई। इस मद में 93212 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सूखाग्रस्त जिलों में 2057 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों में 500 करोड़ रुपए ट्यूबवेल निर्माण के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड में सात विशिष्ट मंडियों को खोलने के मद में 434 करोड़ रुपए रखे गए हैं। राज्य में समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए 897 करोड़ रुपए और दुर्घटना बीमा योजना के लिए 240 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कृषि को पर्याप्त बिजली देने के लिए भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 16 घंटे बिजली देना तय किया है। सौर ऊर्जा से संचालित राजकीय नलकूप भी बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ किया है और अब गन्ना किसानों को भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने चीनी मिलों को 1152 करोड़ रुपए और गन्ना समितियों के कमीशन की प्रतिपूर्ति के लिए 442 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। राज्य में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए चालू परियोजना को आगे के लिए भी विस्तार दिया गया है। इस योजना को पहले से ही बुंदेलखंड के बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, झांसी, और ललितपुर में चलाया जा रहा है। इसके अलावा निशुल्क बोरिंग योजना के तहत बड़े पैमाने पर बोरिंग का काम चल रहा है। अखिलेश सरकार की लगातार कोशिश है कि कृषि और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। सरकार राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए गोमती, सेंगर, अरैया, चंद्रप्रभा, अखेरी, और हिंडन नदी पर कार्य रही है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अंतर्गत 3000 नलकूपों के निर्माण के साथ ही आवागमन की बेहतर सुविधा के लिए नहरों की पटरियों को भी पक्का किए जाने का काम त्वरित गति से किया जा रहा है। वहीं राज्यभर में मौजूद करीब 40 हजार तालाबों को भी पुनर्जीवित किया जा रहा है। सरकार ने किसानों के हितों में कई फैसले किए हैं, इनमें 'मानसून फसल प्रबंधन' भी शामिल है, जिसके तहत विषमकारी हालातों से निपटने के लिए फसल प्रबंधन की रणनीति बनाई गई है और किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में खेती और किसानों की बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के साथ आलू, अनाज फल, सब्जी, दूध आदि की बड़ी मंडियों की स्थापना की जाएगी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार कृषि और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की निरंतर निगरानी और समीक्षा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों का अमला विकास योजनाओं को पूरा कराने में लगा हुआ है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।

28-3-16

प्रभारी, समाचार पत्र प्रकोष्ठ